

न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बर्डजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 17/2024/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांक: 19.2.2024

अन्तर्गत धारा: 18 आर्म्स एक्ट

उनवान

प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र मूल सिंह शर्मा निवासी खेल मैदान के पास माटून्दा तहसील व जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट



उपस्थित : श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक -अपीलार्थी
पैरोकार सरकार -रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृति के संबंध में पारित आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2023/445 दिनांक 17.1.2023 (संक्षेप में अपीलाधीन आदेश) के विरुद्ध यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं, कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 14.6.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, बूंदी एवं पुलिस अधीक्षक सीआईडी (इन्टे0) कोटा तथा उप वन संरक्षक बूंदी से रिपोर्ट चाही गई जिसके क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नहीं की जाने से जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2023/445 दिनांक 17.1.2023 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा में इस आशय की पेश की गई कि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का आदेश विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। जेरअपील आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है जबकि अपीलांत के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। बिना आधार के आवेदन पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलांत को अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलांत के विरुद्ध कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है। ना ही ऐसा कोई उल्लेख सबधित रिपोर्ट में है। स्पष्ट कारण अंकित किये बिना अपीलांत का आवेदन पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश दिनांक 17.1.2023 अपास्त किया जावे तथा अपीलांत का आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमानुसार नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का आदेश विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। जेरअपील आदेश स्पीकिंग


सभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आदेश नहीं है। आदेश में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। स्पष्ट कारण अंकित किये बिना अपीलान्त का आवेदन पत्र खारिज किया है जबकि अपीलान्त के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। बिना आधार के आवेदन पत्र को खारिज करना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्त को अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अंत में अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

- 4 रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
- 5 पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पोजेन्ट पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति में शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित में क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
- 6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 14.6.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, बूंदी एवं पुलिस अधीक्षक सीआईडी (इन्टे0) कोटा तथा उप वन संरक्षक बूंदी से रिपोर्ट चाही गई जिसके क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंसा नहीं करने से अपीलार्थी का आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2023/445 दिनांक 17.1.2023 से खारिज किया गया। हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का आदेश विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। जेरअपील आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। आदेश में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। स्पष्ट कारण अंकित किये बिना अपीलान्त का आवेदन पत्र खारिज किया है जबकि अपीलान्त के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। बिना आधार के आवेदन पत्र को खारिज करना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्त को अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क के संबंध में जेरअपील आदेश एवं जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 3.8.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रिपोर्ट में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं है। जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी ने भी स्पष्ट कारण अंकित किये बिना आलौच्य जेरअपील आदेश दिनांक 17.1.2023 से अपीलान्त के नवीन शस्त्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2023/445 दिनांक 17.1.2023 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलान्त द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 14.6.2022 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में नये सिरों से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक स्पीकिंग आदेश पारित करे।
- 7 निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सारे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजौरिया)

संभागीय आयुक्त
कोटा

कोटा संभागीय आयुक्त